

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक दिए गए अनुदान (लाख रुपयों में)

	1980-81	1981-82	1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	5.76	12.70	वर्ष 1982-83 के लिए
2. असम	2.00	10.85	सम्बन्धित राज्य सर-
3. गुजरात	—	2.00	कारों/संघ शासित
4. केरल	5.00	—	क्षेत्रों से प्रस्ताव
5. नागालैण्ड	0.22	0.59	आमंत्रित कर लिए
6. उड़ीसा	0.24	0.69	गए है ।
7. मणिपुर	0.87	—	
8. त्रिपुरा	—	0.02	
9. मिजोरम	0.79	0.90	

Production performance of Indian Shipyards

3211. SHRI K. A. SWAMI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state details of actual improvements in production performance of Indian Shipyards over the last three years?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): The actual production in the two Shipyards under the control of this Ministry during the last three years is as follows:—

Year	Hindustan Shipyard Ltd.	Cochin Shipyard Ltd.
1979-80	33,110 DWT	22,352 DWT
1980-81	22,790 DWT	36,754 DWT
1981-82	19,780 DWT	53,056 DWT
1982-83 (anticipated)	66,650 DWT	77,000 DWT

सभी स्कूलों में योग प्रशिक्षण का अनिवार्य किा जाना

3212. श्री राम चारे पनिका : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश के सभी स्कूलों में चालू वर्ष से योग प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कुल कितने योग अध्यापकों की आवश्यकता होगी और इस समय ऐसे कितने अध्यापक उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास योग अध्यापकों का कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) योग का एक स्वतन्त्र विषय के रूप में, प्रयोगात्मक आधार पर सभी केन्द्रीय विद्यालयों (केन्द्रीय स्कूलों) में 1981-82 के शैक्षणिक सत्र से आरम्भ किया गया है। दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में योग को शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया गया है। योग को एक स्वतन्त्र विषय के रूप में, केन्द्रीय विद्यालयों के अलावा विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में शुरू करने सम्बन्धी प्रश्न की केन्द्रीय विद्यालयों में योग का प्रयोगात्मक रूप में आरम्भ करने के परिणामों को देखते हुए तथा राज्य सरकारों के परामर्श से जांच करनी होगी।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में शत-प्रतिशत साक्षरता

3213. श्री चतुर्भुज : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से राजधानी में शत-प्रतिशत साक्षरता की योजना तैयार करने का है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जनगणना निदेशक, दिल्ली के अनुसार 1971 तथा 1981 के दौरान जनगणना में

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के साक्षरता दर क्रमशः 56.61 प्रतिशत तथा 61.06 प्रतिशत थी। 1981 के लिए साक्षरता की दर अभी भी अस्थायी है।

(ख) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उपलब्ध प्रशासनिक तथा वित्तीय संसाधनों तथा उसके तत्सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली में, औपचारिक स्कूलों, प्रौढ़ स्कूलों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, समाज शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि के माध्यम से साक्षरता की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, पड़ोसी राज्यों से उत्प्रवास/लोगों के आगमन और दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि से निश्चय-पूर्वक यह बताना सम्भव नहीं है कि किस समय तक शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली जाएगी।

मजफ्फरपुर रेल सेवा आयोग में दैनिक मजूरी भोगी चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों को नियमित किया जाना

3214. श्री आर. एन. राकेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर रेल सेवा आयोग में अनेक वर्षों से कार्यरत भैकड़ों दैनिक मजूरी भोगी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दैनिक मजूरी भोगी श्रमिक कितने हैं और वे कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन श्रमिकों द्वारा प्रदान की गई लम्बी अवधि की सेवा का ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार इनकी सेवा नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?